

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -675/2010/कोटा

मैसर्स अग्रवाल फ्लोरिंग स्टोन सिंडीकेट माईन्स,
पीपाखेड़ी, रामगंज, कोटा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,कोटा।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अधिवक्ता।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक:-13.04.2015

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी जो अपील संख्या 06/वेट/2009-10/झालावाड़ के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा)की धारा 23, 24 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2009 के तहत "कोटा स्टोन" केक उत्खन्न के लिये प्रयुक्त "केप्टिल गुड्स" की खरीद पर चाहे गये आगत कर की मुजरा राशि रु.5,32,178/- की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी खनन ईकाई होने के बावजूद अविधिक रूप से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर आगत कर की मुजरा राशि का क्लेम किया गया है जबकि उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार देय नहीं है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, आदेश दिनांक 26.03.2009 पारित किया गाय। उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील

लगातार.....2

प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विनिर्माणकर्ता है एवम् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान माईनिंग व विनिर्माण की संश्लिष्ट गतिविधि की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त उत्पाद होने से अपीलार्थी विनिर्माता की श्रेणी में आता है। इसी कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खनन हेतु प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किये गये वेट का अधिनियम की धारा 18 के तहत आगत कर का मुजरा उचित रूप से चाहा गया था। अग्रिम कथन किया कि कोटा स्टोन के ब्लॉक्स को खान में से निकाल कर, उसकी विशिष्ट साईज (लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई) में कटाई करना विनिर्माण की परिभाषा में आता है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभाग से निर्माणकर्ता के रूप में पंजीयन दायित्व लिया गया है एवम् पूंजीगत वस्तुओं के रूप में मशीनों का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण में है जिसके कारण पूंजीगत वस्तुओं पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विधिक रूप से आगत कर की मुजरा राशि चाही गयी थी जिसे दोनों अवर अधिकारियों द्वारा अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा खनन कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने वाले उपकरण/औजार/सामग्री पर रिवर्स किये गये आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत 61 एस.टी.सी. 264, 47 एस. सी. 124, 11 एस.टी.सी. 188, 122 एस.टी.सी. 207, 5 टैक्स अपडेट 122, 13 टैक्स अपडेट 256 को प्रोद्धरित कर, प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित प्रतिपादित सिद्धांत के आलेक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के तहत आगत कर क्लेम उसी स्थिति में ही देय है, जब राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से कर योग्य माल क्रय कर पुनः उक्त माल का विक्रय राज्य/अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में किया जाता है अथवा कोई वस्तु कच्चे माल के रूप में क्रय कर उससे निर्मित नयी वस्तु राज्य/अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय/निर्यात करता है अथवा कर योग्य माल क्रय कर राज्य में पूंजीगत वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खनन कार्य किया जाता है। अतः खनन

la

2/

कार्य में व खनन प्रक्रिया के प्रयोजनार्थ काम आने वाली मशीनों पर अदा किये गये वेट की राशि का आगत कर की मुजरा राशि अधिनियम की धारा 18 के तहत अनुज्ञात नहीं किया जा सकता।

विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया खनन कार्य अधिनियम की धारा 2(22) के प्रावधानानुसार परिभाषित निर्माता (Manufacture) की श्रेणी में नहीं आने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के दौरान खनन प्रक्रिया हेतु पूंजगत वस्तुओं के क्रय पर राज्य के पूंजीकृत व्यवहारियों को अदा किये गये वेट का आगत कर का मुजरा अस्वीकार करने संबंध में पारित निर्धारण अधिकारी का आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम् मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट, सिरोही बनाम् अपील संख्या -1319/2013/सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर माननीय पीठ द्वारा खनन कार्य में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर की मुजरा राशि को अस्वीकार किया गया है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलेक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "कोटा स्टोन" के उत्खन्न के लिये प्रयुक्त "केपिटल गुड्स" की खरीद पर अदा किये गये वेट का आगत कर का मुजरा चाहा गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 2(22) के तहत विनिर्माण, धारा 2(29) के तहत कच्चा माल एवं धारा 2(7) के तहत पूंजीगत वस्तुओं (केपिटल गुड्स) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जिन्हें अधिनियम में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

(22) "manufacture" includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government.

2(7) "Capital Goods" means plant and machinery including parts and accessories thereof, meant for use in manufacture unless otherwise notified by the State Government from time to time in the official Gazette.

2(29) "raw material" means goods used as an ingredient in the manufacture of other goods and includes processing material, consumables, preservative, fuel





and lubricant required for the process of manufacture;

निर्माण की परिभाषा के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि माईनिंग में कोई पृथक एवं विशिष्ट रूप से भिन्न वस्तु नहीं निर्मित होती है, इसलिए माईनिंग/खनन को विनिर्माण की प्रक्रिया नहीं माना गया है।

जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, उक्त हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि जहां तक खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों पर चुकाये गये कर का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानान्तर्गत जो निम्नांकित है, आगत कर का मुजरा देय नहीं होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त को अस्वीकार किया गया है।

अधिनियम की धारा 18.- Input Tax Credit. - (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

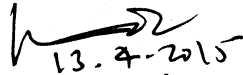
- (a) sale within the State of Rajasthan; or
- (b) sale in the course of inter-State trade and commerce; or
- (c) sale in the course of export outside the territory of India; or
- (d) being used as packing material of the goods, other than exempted goods, for sale; or
- (e) being used as raw material, "*except those as may be notified by the State Government,*" in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of inter-State trade or commerce; or
- (f) "*being used as packing material of goods or as raw material in manufacture of goods for sale*" in the course of export outside the territory of India; or
- (g) **being used in the State as capital goods;** however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section. (09.03.2011 से पूर्व की स्थिति में)

अधिनियम के उक्त प्रावधानानुसार कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुयें, जो कि वि-निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होंगी, उन्हीं पर ही आगत कर का मुजरा देय होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2(7) में वर्णित "पूंजीगत वस्तु" की परिभाषा से स्पष्ट है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निर्माण प्रक्रिया से अन्यथा प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर आगत कर का मुजरा संबंधी प्रावधान अधिनियम में नहीं हैं।


यही नहीं अपीलार्थी द्वारा खनन में प्रयुक्त मशीनरी विनिर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती हैं, बल्कि केवल उत्खनन में ही प्रयुक्त होती हैं तथा उत्खनन निर्माण प्रक्रिया नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अन्ततः निर्माण कार्य किया जाता है जिसमें खनन प्रक्रिया निर्माण के पूर्व की प्रक्रिया है। अतः समग्र तौर पर उक्त पूंजीगत माल निर्माण कार्य में प्रयुक्त हुआ है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त पूंजीगत वस्तुयें पूर्ण रूप से खनन कार्य में ही प्रयुक्त हुयी हैं। फलस्वरूप, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह पीठ यह अवधारित करती है कि आगत कर का मुजरा केवल वि-निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं (Capital Goods) पर देय होगा अन्य प्रक्रियाओं में प्रयुक्त वस्तुओं/माल पर देय नहीं होगी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व हस्तगत प्रकरण के तथ्य पूर्णतः भिन्न प्रकृति के होने के कारण हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। फलस्वरूप, उक्त विश्लेषण व कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1450/2011/उदयपुर व अपील संख्या 2142/2012/उदयपुर निर्णय दिनांक 17.02.2014, व विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त-द्वितीय, जयपुर बनाम मैसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेन्ट, सिरोही बनाम अपील संख्या -1319/2013/सिरोही निर्णय दिनांक 26.06.2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से मांग राशियां कायम की गयी हैं। जिन्हें अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


13.4.2015
(मदन लाल)

सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष